छोड़ देना है, यह दुर्घटनाओं में लगी चोटों की गम्भीरता पर निर्भर करता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Pay Commission for L.I.C. Employees

1502. Shri Vishram Prasad:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have directed the Chairman of the Life Insurance Corporation of India to appoint a Pay Commission to make recommendations regarding the dearness allowance and conditions of service of the employees of the Life Insurance Corporation;

(b) whether the Commission has since been set up;

(c) if so, the terms of reference of the Commission; and

(d) if the reply to part (b) above be in the negative, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

(d) Matters relating to dearness allowance and conditions of service are discussed by the Corporation with the Employees' Associations, and decisions are taken on the basis of such discussions with the approval of Government. There has been no need to consider the appointment of a Pay Commission.

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

1503. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने क्वार्टर तैयार हो चुके हैं; जो बिजली तथा पानी की व्यवस्था न होने के कारण सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिये गये;

(ख) ये कितने समय से खाली पड़े हैं;

(ग) पानी तथा बिजली की व्यवस्था करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(घ) उन को दिये जाने के योग्य बनाने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) इस अवधि में कितने किराये की हानि हुई है और इस के लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सेहर चन्द खन्ना): (क) से (ङ). पिछले वर्ष रामकृष्णपुरम में लगभग 3,000 क्वार्टर करीब-करीब तैयार हुए थे । दिल्ली नगर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्था कर देने के बाद इन में से लगभग 2,000 क्वार्टर आवंटित कर दिये गये हैं । शेष 1,000 क्वार्टरों के लिए नगर निगम के द्वारा पानी की सप्लाई की व्यवस्था अभी की जानी है । पानी की व्यवस्था हो जाने पर चार से छः सप्ताह के समय में क्वार्टरों को रहने योग्य बनाया जा सकता है । किराये की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि पानी की व्यवस्था न होने पर क्वार्टरों का दखल नहीं लिया जा सकता था ।

Mitra Committee's Report on Dowlaishwaram Anicut over the Godavari

1504. Shri Kolla Venkaiah:
Shri M. N. Swamy:
Shri Laxmi Dass:
Shri Shree Narayan Das:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply